खेल विशेषज्ञता का लाभ युवाओं तक पहुंचे

सीएम ने स्पेन यात्रा के पहले दिन मैड्रिड में लॉलीगा मुख्यालय का किया दौरा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी स्पेन यात्रा के पहले दिन की शुरूआत मैड्रिड स्थित विश्व प्रसिद्ध लॉलीगा मुख्यालय के भ्रमण से की और वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर खेल, युवा सशक्तिकरण और निवेश सहयोग पर केंद्रित संवाद किया.

उन्होंने कहा कि लॉलीगा की खेल विशेषज्ञता और वैश्विक पहुंच का लाभ मध्यप्रदेश के युवाओं तक पहुंचना चाहिए. यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि खेल के क्षेत्र में नवाचार,

सामाजिक समावेशन और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की दिशा में प्रदेश के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लॉलीगा के पदाधिकारी और तकनीकी निदेशकों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि मध्यप्रदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर फुटबॉल एक्सीलेंस सेंटर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन और स्पेनिश कोचिंग आधारित यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ किए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि लॉलीगा के साथ यह साझेदारी केवल खेलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह प्रदेश में रोजगार सृजन, सामाजिक भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और सांस्कृतिक पर्यटन को नई दिशा दे सकती है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सुझाव दिया कि लॉलीगा मैचों के दौरान डिजिटल और ग्राउंड को-ब्रांडिंग अभियानों के माध्यम से मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, वन्यजीव, विरासत स्थलों और पर्यटन अवसरों का स्पेन और यूरोप के व्यापक दर्शकों के बीच प्रभावी प्रचार किया जा सकता है. इससे न केवल पर्यटन बल्कि स्पोर्ट्स टूरिज्म, फिटनेस, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग और स्पोर्ट्स टेक जैसे सेक्टर्स में विदेशी निवेश आकर्षित करने की संभावनाएं मजबूत होंगी.

लॉलीगा और मप्र भविष्य के साझेदार

लॉलीगा स्पेन की प्रमुख पेशेवर फुटबॉल लीग, न केवल स्पोर्टिंग उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर युवाओं के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और ब्रांड विस्तार का भी एक प्रभावशाली मंच है. भारत में लॉलीगा की सक्रियता, विशेषकर लॉलीगा फुटबॉल स्कूल जैसी पहल, यह दर्शाती हैं कि स्पेनिश फुटबॉल का भारतीय युवाओं से गहरा संबंध बन चुका है. अब यह संबंध मध्यप्रदेश जैसे संभावनाशील राज्य के लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकता है.

सीएम ने हरदा छात्रावास की घटना पर रिपोर्ट तलब की

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 जुलाई. हरदा के एक होस्टल में पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदेश के राजपूत समाज में गहरी नाराजगी है. ये मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता हैं, वहीं इस मामले में कांग्रेस भी सरकार से सवाल पूछ रही है. लिहाजा स्थिति की नजाकत को समझते हुए सरकार अब बैकपुट पर है और डैमेज कंट्रोल में जुट गई है.

इधर विदेश यात्रा कर रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी मामले को संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन हरदा से मामले की विस्तृत जांच कर डिटेल रिपोर्ट तलब की है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाकायदा एक्स पर ट्वीट पर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामाजिक न्याय और परस्पर सद्भाव बना रहे, यही हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी. हरदा में दो दिन पहले करणी सेना ने एक मामले को लेकर आंदोलन किया था. इस

पुलिस की कार्रवाई से से राजपूत समाज नाराज

अब डैमेज कंट्रोल में जुटी राज्य सरकार

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया था, इस दौरान लाठीचार्ज भी किया गया था. लाटीचार्ज से बचने के लिये राजपूत समाज के प्रदर्शनकारी पास के एक होस्टल पहुंच गये थे. यहां भी पुलिस पहुंच गई थी और यहां नाम पूछकर राजपूत समाज के प्रदर्शनकारियों की जमकर पिटाई की थी, इस घटना से पूरे प्रदेश के राजपूत समाज में नाराजगी फैल गई. इस मामले ने बाद में राजनीतिक रूप भी ले लिया. कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हरदा घटना का बाकायदा वीडियो सोशल मीडिया में जारी कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाये और इसे बर्बर कार्रवाई करार दिया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी पुलिस कार्रवाई पर तीखे सवाल उठाये हैं.

इधर घटना के बाद राजपूत समाज से भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने भाजपा और सरकार से सवाल पूछ लिया है कि क्या राजपूत समाज हिंदू नहीं है. राजपूत समाज ने तो बाकायदा मप्र मानव अधिकार आयोग की भी शरण ली है और मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई का अनुरोध किया है. इधर राजपूत समाज का विरोध प्रदर्शन मप्र की सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में भी पहुंच गया है और वहां के संगठनों ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की है. ऐसे में राज्य सरकार भी बैकपुट पर है. मामले को लेकर आने वाले दिनों में राज्य सरकार घटना के लिये दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है.

सचदेवा आज लेंगे चीफ जस्टिस पद की शपथ

भोपाल, 16 जुलाई. मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किये गये न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा गुरुवार को मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे.

राजभवन में संक्षिप्त और गरिमामय कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे. समारोह प्रात: 10 बजे सांदीपनि सभागार में होगा. न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा बुधवार दोपहर को राजधानी पहुंच गये हैं. राजभवन में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा का राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया.

इस अवसर पर राजभवन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मनोनीत न्यायमूर्ति सचदेवा का स्वागत किया. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रदेश के मंत्री, हाईकोर्ट के जस्टिस, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे.

प्रदेश के 9500 स्कूलों में बिजली नहीं

पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

भोपाल, 16 जुलाई. मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

उन्होंने केंद्र सरकार के एक रिपोर्ट के हवाले से राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भयावह और चिंताजनक बताया है. पटवारी ने पत्र में लिखा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत संचालित यूडाइस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) की वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश की शिक्षा संबंधी मूलभूत समस्याएं उजागर

हुई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के करीब 9500 सरकारी स्कूलों में अब भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है. वहीं 12 हजार से अधिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरी कक्षा की पढ़ाई हो रही है. कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाया है कि जब सरकार के पास पर्याप्त बजट और प्रशासनिक ढांचा मौजूद है, तो फिर बच्चों को बिजली, शिक्षक, फर्नीचर और शौचालय जैसी न्यूनतम सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस रिपोर्ट को विधानसभा के आगामी सत्र में गंभीरता से उठाया जाए, साथ ही शिक्षा बजट के उपयोग और दुरुपयोग की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, ताकि वास्तविक जिम्मेदारी तय की जा सके.

इंदौर में किन्नर समुदाय के दो गुटों में विवाद

इंदौर. शहर में किन्नर समुदाय के दो गुटों के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. हिंदू किन्नर समूह की प्रतिनिधि सपना गुरु ने मालेगांव से आए कुछ किन्नरों पर धर्मांतरण कराने और एचआईवी संक्रमण फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. सपना ने इस मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, पीएमओ और सुप्रीम कोर्ट तक की है. सपना का कहना है कि डर के कारण कई किन्नर अपना ठिकाना छोड़ चुके हैं, जबकि कुछ दबाव में आकर आरोपित गुट में शामिल हो गए हैं. उन्होंने दावा किया कि करीब 60 किन्नर संक्रमित हो चुके हैं और उनमें से 12 का इलाज एमवाय अस्पताल के एआरटी सेंटर में चल रहा है.

प्रदेश में खाद संकट पर गरजे कमलनाथ

चिंताजनक स्थिति पर बोले- किसानों को ससम्मान खाद दें

छिंदवाड़ा, 16 जुलाई. मध्य प्रदेश में एक बार फिर खाद संकट गहराता जा रहा है. छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में किसान लंबी-लंबी कतारों में खड़े होकर भी खाद के लिए भटक रहे हैं. इस स्थिति पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है.

कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा में सुबह से ही किसान खाद वितरण केंद्रों पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रहा. एक वीडियो सामने आया है, जिसमें किसानों की भीड़ स्पष्ट दिखाई दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन खाद देने की

बजाय सख्ती बरत रहा है, जिससे नाराज होकर कई किसान सड़क पर बैठ गए.

कमलनाथ ने प्रशासन से तत्काल सम्मानजनक वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है. उन्होंने कहा, जब यह सर्वविदित है कि इसी समय किसानों को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो पहले से पर्याप्त भंडारण और वितरण की योजना क्यों नहीं बनाई गई?

उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ऐसा लगता है कि सरकार ने किसानों को तंग करना ही अपना कर्तव्य समझ लिया है. कांग्रेस यह अन्याय सहन नहीं करेगी और देश के अन्नदाता के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. प्रदेश में लगातार बढ़ती खाद की मांग और किल्लत ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

एमपी में फिर मेहरबान बादल, खूब बरसेंगे

भोपाल, 16 जुलाई. मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मंगलवार को हुई हल्की बारिश के बाद बुधवार से स्ट्रॉन्ग मॉनसून सिस्टम सक्रिय हो रहा है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 8 इंच तक वर्षा की संभावना जताई गई है. वहीं, गुना, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, शहडोल, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट सहित 14 जिलों में येलो अलर्ट है, जहां 4 इंच तक बारिश हो सकती है. शेष जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. अब तक प्रदेश में औसतन 18.5 इंच वर्षा हो चुकी है.

जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों में 86 प्रतिशत से अधिक बारिश, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और नर्मदापुरम संभागों में 57 प्रतिशत ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है. मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने, निचले इलाकों में आवागमन से बचने और जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है.

पेज एक का शेष

भारत-स्पेन जुड़वा भाइयों की तरह : डॉ. मोहन

मध्यप्रदेश आंतरिक सड़कों, नेशनल हाईवेज, रेल और हवाई मार्ग से देश-विदेश से जुड़ा है. मप्र सभी सेक्टर्स में तेजी से आगे बढ़ने वाला भारत का राज्य बना है. हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मप्र में फूड प्रोसेसिंग, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री और टेक्सटाईल सेक्टर में बड़ी संभावनाएं हैं. हम सभी सेक्टर्स में यहां आने वाले निवेशकों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की क्षमता रखते हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों से आग्रह किया कि सुरक्षित निवेश के लिए आप बेहिचक मध्यप्रदेश से जुड़िए. हमारी 18 प्रकार की हाईटेक औद्योगिक नीतियों का लाभ लें. मप्र निवेशकों को केपिटल रिटर्न देने में पीछे नहीं रहेगा. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश की विकासशीलता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी प्रभावित किया है. मध्यप्रदेश में निवेश करने पर भारत सरकार की ओर से भी देशी-विदेशी निवेशकों को कई तरह की रियायतें दी जा रही हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या भी तेजी से बढ़ाई जा रही है और नई मेडिकल डिवाईसेस के लिए देशी और विदेशी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं. अब मध्यप्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है. इस दौरान मप्र के अफसरों ने प्रेजेंटेशन भी दिया.

अफसर हटाओ, जांच कराओ

दिग्विजय ने उठाया सवाल

हरदा, 16 जुलाई. मध्यप्रदेश के हरदा जिले में शनिवार को करणी सेना के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और बल प्रयोग का मामला अब सियासी रंग ले चुका है.

धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी को कथित रूप से संरक्षण देने के आरोपों के विरोध में करणी सेना द्वारा सिटी कोतवाली थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया, जहां स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर किया. इस दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. हालांकि बाद में शेरपुर को सशर्त रिहा कर दिया गया. लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है. घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर वीडियो साझा कर हरदा के कलेक्टर और एसपी को हटाने की मांग की है. उन्होंने इस मामले की न्यायिक जांच कराने की भी अपील की है.

प्रक्रिया में बदलाव | ओवर ब्रिज, फ्लाय ओवर में लगातार खामी के बाद लिया निर्णय

लोनिवि के इंजीयिरों को अब ट्रेनिंग देगी सरकार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 जुलाई. प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों द्वारा तैयार किये गये पुल, ओव्हर ब्रिज, फ्लाय ओवर आदि के डिजाइन और निर्माण में लगातार खामी आने के बाद अब राज्य सरकार प्रदेश के इंजीनियरों को और दक्ष बनाएगी, जिससे कि उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़े और नई तकनीक के साथ वे बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सके.

इसके लिए उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जायेगी. इसके लिये मप्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तकनीकी सलाहकार को इंडियन अकादमी फॉर हाईवे इंजीनियरिंग के साथ मिलकर पुलों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. राज्य के सभी अभियंताओं को इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी कोड्स और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मोर्थ के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर उनके आधार पर कार्यों का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए हैं.

ब्रिज परियोजनाओं के गुणवत्तापूर्ण निर्माण, मापदंड अनुसार डिजाइन, सतत सुपरविजन प्रणाली अपनाने एवं निर्माण के दौरान सतत निरीक्षण के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. रेलवे अथवा नगर निगम जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है. मुख्य अभियंता सेतु परिक्षेत्र पीसी वर्मा द्वारा के मुताबिक पुराने अलाइनमेंट्स को रद्द नहीं किया गया है अपितु गलती से जारी हुआ एक त्रुटिपूर्ण आदेश उसी दिन निरस्त कर दिया गया. उल्लेखनीय है कि पुलों और फ्लायओवर की जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग (जीएडी) रेलवे और लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती हैं.

निर्माण के दौरान स्टेकहोल्डर्स से समन्वय जरुरी

राज्य शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि निर्माण के दौरान होने वाले सभी परिवर्तन अन्य स्टेकहोल्डर्स जैसे नगर निगम और रेलवे के समन्वय से ही किए जाएं. ब्रिज परियोजनाओं में आने वाली जटिल बाधाओं के शीघ्र निराकरण के लिये प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें आवश्यकता अनुसार शासकीय या निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है. अब समस्याओं का तकनीकी स्तर पर शीघ्र समाधान हो सकेगा और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14